भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1941

जिसका उत्तर 14 मार्च, 2022/23 फाल्गुन, 1943 (शक) को दिया गया

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का विनिवेश

1941. श्री डी. एम. कथीर आनन्द:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के अधिकांश बैंकों (पीएसबीएस) का वर्ष 2023-24 के अंत तक विलय या विनिवेश किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तमिलनाडु में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पीएसबी की कुल संख्या कितनी है;

(ग) तमिलनाडु में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में तमिल भाषा के ज्ञान वाले बैंक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा विशेष रूप से तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क): वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के अपने केंद्रीय बजट भाषण में सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों (पीएसबी) का निजीकरण करने और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) में कार्यनीतिक विनिवेश की नीति का अनुमोदन करने के सरकार के इरादों की घोषणा की थी। आत्मनिर्भर भारत के लिए नयी पीएसई नीति के अनुसार, नीति के उद्देश्यों में निजी पूंजी का निवेश सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को विकसित करना शामिल है ताकि वे आर्थिक विकास और नये रोज़गार और सामाजिक क्षेत्र में वित्तपोषण और सरकार के विकास कार्यक्रमों में योगदान दे सकें। इसके अलावा, पीएसबी के निजीकरण संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा पीएसबी के निजीकरण पर निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख): भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु में पीएसबी की कुल 6275 शाखाएं परिचालनरत थीं, जिनमें से 1869 शाखाएं ग्रामीण इलाकों में, 897 शाखाएं शहरी इलाकों में और 3509 शाखाएं अन्य इलाकों (महानगर व अर्ध शहरी) में थीं।

(ग): अधिकारियों की नियुक्ति अखिल भारतीय आधार पर की जाती है और उन्हें पूरे भारत में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है, इसलिए वे बैंक अधिकारियों के लिए क्षेत्रीय भाषा में सम्पर्क कौशल सीखने के लिए तमिल सहित भाषा संबंधी कार्यशालाएं आयोजित करते हैं, जिसका उद्देश्य स्थानीय लोगों के लिए सुलभ होना और उन्हें

गुणवत्ता युक्त बैंकिंग सेवाएं देना है। इसके अतिरिक्त, बैंकिंग सेवाओं की सहज उपलब्धता के लिए और इसमें भाषा बाधक न बने यह सुनिश्चित करने के लिए बैंकों ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

1. सभी काउंटरों पर संकेतक बोर्डों को हिन्दी व अंग्रेज़ी भाषा के अलावा तमिल में प्रदर्शित किया जाना।
2. सेवाओं और सुविधाओं के सभी विवरणों वाली बुकलेट तमिल भाषा में में उपलब्ध कराना।
3. खाता खोलने के फॉर्म, पासबुक आदि के सहित ग्राहकों द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी मुद्रित सामग्रियां तमिल भाषा में उपलब्ध कराना।
4. ग्राहक शिकायतों का समाधान तमिल में उपलब्ध कराना।
5. राज्य में लगाए गए सभी एटीएम में ग्राहकों के लिए तमिल भाषा के उपयोग का विकल्प उपलब्ध कराना।
6. विभिन्न बैंकों में तकनीकी-समर्थित स्मार्ट बैंकिंग डिजिटल चैनल जैसे मोबइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और कॉल सेंटर सेवाओं की उपलब्धता दी जाने वाली सेवाओं की संख्या, ग्राहकों के साथ मित्रवत व्यवहार और स्थानीय भाषा में ग्राहक-इंटरफेस को बढ़ाने में मदद की है।

(घ): तमिलनाडू के ग्रामीण इलाकों सहित आम लोगों को गुणवत्ता युक्त बैंकिंग सेवाएं देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए क़दम निम्नलिखित हैं :

1. प्रत्येक गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक बैंकिंग आउटलेट, शाखा या बैंक मित्र की उपलब्धता सुनिश्चित करके पूरे देश में अभिचिह्नत 99.96% रिहायशी गांवों को कवर किया जा सका है जिससे बैंकिंग सेवाओं का सहज सुलभता (ईज़ ऑफ एक्सेस) सुदृढ़ हुई है।
2. जैम त्रियामी व्यवस्था (खाताधारकों के आधार और मोबाइल से लिंक किए गए जनधन खाते) ने जनसंख्या के अन्यथा बैंकिंग-रहित वर्ग के लिए बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की है और बैंकिंग के लिए इन नये ग्राहकों को धन-प्रेषण, जमा और बीमा उत्पादों की सुविधा उपलब्ध कराने के अलावा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूप में सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाया है।
3. पीएसबी सुधार एजेंडा ईज़ को लागू करने से अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित संभव हो पाया है :
    i. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ऋण प्रबंधन प्रणाली और केंद्रीकृत प्रोसेसिंग केंद्रों और सूक्ष्म-उद्यमों को ऋण के लिए एंड-टू-एंड ऑटोमेटेड डिजिटल लेंडिंग को आरंभ करने से ऋणों की प्रोसेसिंग और संस्वीकृति के टर्न-अराउंड-टाइम (टैट) में सुधार संभव हो पाया है।
    ii. एमएसएमई ऋणों, आवास ऋणों, व्यक्तिगत ऋणों और वाहन ऋणों को ऑनलाइन सैद्धांतिक अनुमोदन देने के लिए PSBloansin59minutes.com के माध्यम से डिजिटली ऋण देने की शुरुआत करने से आम श्रमिक वर्ग सहित व्यक्तियों की ऋण तक पहुंच में सुधार हुआ है।
4. वित्तीय सेवाओं के विकास के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान चलाने और ऋण वृद्धि को बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रसार करने के उद्देश्य से ऋण लोकसंपर्क कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।
5. ग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज सहित बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में आम लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए नियमित अंतरालों पर वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन किया गया।

*****